meet the railway's requirements of points crossings, structurals, etc. One difficulty that he pointed out is correct. For the complete rehaul of the old machinery an investment of Rs. 63 lakhs is necessary. We are trying to make necessary provisions and I can assure him that for want of financial resources the overhauling of that factory will not suffer. One more assurance I can give: on the basis of the availability of resources we will try to have full utilisation of installed capacity of the Arkonam workshop.

SHRI M. KALYANASUNDARAM. I am glad that the Railway Minister has come out with an assurance that this workshop will be utilised to its full capacity.

But regarding the hand-signal lamp, he made it appear, in the information given by him, that the market purchases were cheaper by more than 50 per cent, and that the lamps produced in the Arkonam workshop cost more than double. Is he aware that such lamps are not produced by the private sector on any commercial basis? They are peculiar only to the Railways When Mr. Alagesan and myself went to that workshop, we were informed by the workers themselves that the private sector does not produce any lamps. They purchase the condemned lamps from the Railways and repair them and sell them to the Railways. That is why they are cheaper by 50 per cent; and the very next year they come to the same workshop for repairs. If it is a fact, will the hon. Minister enquire into this and see that the hand signal lamps are also produced efficietly at Arkonam?

PROF. MADHU DANDAVATE: As far as the first part of the question is concerned, we will really enquire in to the matter. If what he has been saying is the state of affairs, it is then really a difficult position; and we will have to check it. I will enquire into it. As far as the second part of the question is concerned, I must repeat that our priority at the present stage when we want to strengthen maintenance of the railway tracks is that we want to concentrate more on the manufacture of track materials, point structures etc. And at this stage it will not be possible for me to give that assurance as far as signal hand lamps are concerned. We will concentrate on them in the new workshop.

डा० रामजी सिंह : क्या रेल मंत्री जी यह बताएंगे कि रेलवे विभाग से जो लैम्प बनाए जाते है उस की कीमत 70 रुपये है लेकिन वह 25 वर्ष चलते हैं तो क्या यह सस्ता सौदा नहीं है और क्या जैसा माननीय अलगेशन साहब ने बताया है कि माडर्नाइजेशन की आवश्यकता है, अगर माडर्नाइजेशन कर दिया जाय तो ये सस्ते पड़ेंगे ? हम को यह लगता है कि हमारे सभी रेलवे वर्कशाप की यही हालत है । जमालपुर रेलवे वर्कशाप में भी यही स्थिति है कि रोलिंग स्टाक का माडर्नाइजेशन नहीं हुआ है और वहां कम चीजें हो रही हैं । लगता है कि रेलवे मन्त्रालय में कुछ ऐसे लोग है जो प्राइवेट एण्टरप्राइजेज को मदद करना चाहते हैं । क्या आरकोणम रेलवे वर्कशाप और जमालपुर रेलवे वर्कशाप की अधोगति को देखते हुए उन का आधुनिकीकरण करने पर मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : जो कार्यवाही के लिए सुझाव है उस पर जरूर विचार करेंगे ।

मुगलसराय में नया रेलवे डिवीजन

*192. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे पर मुगलसराय में एक नया रेलवे डिवीजन बनाया है ;

(ख) क्या उक्त नये डिवीजन के लिए दानापुर डिवीजन से चार सौ कर्मचारियों को भेजने का निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कर्मचारी दानापुर से मुगलसराय नहीं जाना चाहते,

(घ) क्या उन्हें इस बारे मे एक भूतपूर्व संसद् सदस्य तथा बिहार विधान सभा के विपक्ष के नेता की ओर से कोई सुझाव पत्र प्राप्त हुआ है, और

(ङ) यदि हा, तो उसमे क्या लिखा है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) · (क), (ख) और (घ). जी हा ।

(ग) अब तक केवल लगभग 40 कर्मचारी स्थानान्तरण पर गये हैं । अन्य कर्मचारियो से स्थानान्तरण के खिलाफ तथा विभिन्न सुविधाओ की माग के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) श्री राम लखन सिंह यादव ने कर्मचारियो की एक बैठक मे पारित एक सकल्प भेजा है । सकल्प की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है ।

इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

10-8-77 को मडल कार्यालय, दानापुर के कर्मचारियो द्वारा अपनी एक सार्वजनिक बैठक मे सर्वसम्मति से पारित सकल्प ।

वर्तमान दानापुर और धनबाद मडलो से कुछ हिस्सा लेकर मुगलसराय मडल बनाने तथा हवडा मडल का कुछ क्षेत्र दानापुर मे मिला देने की घोषणा को लेकर प्रशासन और कर्मचारियो के दिलो-दिमाग मे काफी घबड़ाहट है । हाल के कुछ दिनो मे दानापुर से कर्मचारियो को अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित करने की एक के बाद एक कई योजनाए बनायी गयी हैं । कर्मचारियो ने किसी न किसी रूप में अपनी शिकायतें प्रशासन तक पहुचायी हैं, परन्तु स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है । अतः, एक ऐसा सर्वसम्मत फार्मूला तयार करने के लिए जिससे अधिक से अधिक कर्मचारियो का हित हो, दानापुर मंडल के सचिवालयी कर्मचारियो की इस सार्वजनिक बैठक में जो 10-8-77 को दानापुर के मडल कार्यालय भवन के द्वार पर दोपहर को विश्राम के समय हुई, उपस्थित कर्मचारियों के विचार के लिए तथा पारित करने के लिए यह सकल्प विधिवत प्रस्तुत किया जाता है ।

मुगल सराय मडल के लिए कर्मचारियो के स्थानान्तरण तथा सवर्ग संरचना के मामले मे कर्मचारियो तथा प्रशासन दोनो के व्यापक हित मे वार्त्ता मत्र अर्थात ई०आर०एम०यू० और ई०आर०एम०सी० की मार्फत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रशासन के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं —

(1) यह कि, दानापुर मडल मे कर्मचारियो की सख्या में कटौती करने से पहले इस मडल का प्रस्तावित क्षेत्र जो मुगलसराय मडल (दानापुर तथा धनबाद मडलो से कुछ भाग लेकर तथा दानापुर मडल मे कुछ भाग मिलाकर) बन जाने के बाद होगा, उसके आधार पर कर्मचारियो की सख्या का समग्र रूप से आकलन किया जाय ।

(2) यह कि, दानापुर मडल मे पुराने मानदड के आधार पर कुछ रिक्तिया पहले से ही है और इनके बारे मे रेलवे बोर्ड के साथ लिखा पढी चल रही है । इसके अतिरिक्त, पिछले कार्य-विश्लेषण के बाद से यहा अब काम भी बहुत अधिक बढ गया है । अतः यहां निर्णायक कार्य विश्लेषण किया जाय तथा रिक्तियो की नवीनतम स्थिति मालूम की जाय ।

(3) यह कि, मुगलसराय मडल मे आने के लिए सभी रेलो के कर्मचारियों से विकल्प मागा जाय ।

(4) यह कि, प्रभावित मडलो (हवड़ा, धनबाद और दानापुर) के कर्मचारियो को

प्रोत्साहन स्वरूप तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देकर, उनसे भी विकल्प मांगा जाय ।

(5) यह कि, उपयुक्त संख्या मे श्रेणी III और श्रेणी IV के पद छोड देने के बदले में अधिकारियो के पद बिल्कुल न बनाये जायें । उपयुक्त संख्या में पद छोड़ देने के बदले मे बनाये गये अधिकारियों के पदो को समाप्त किया जाय ।

(6) यह कि, ऊपर बताये गये मुद्दे अत्यावश्यक मार्ग-दर्शक तथ्य है । हमारा प्रस्ताव है कि नये दानापुर मडल के लिए अपेक्षित कर्मचारियो की वास्तविक सख्या मालूम करने के लिए इसका आकलन पहले ही कर लिया जाय ।

(7) यह कि, यदि फिर भी दानापुर मडल में वर्तमान कर्मचारियो की सख्या परिकलित संख्या से अधिक बैठे, तो अतिरिक्त पदो को कनिष्ठता के आधार पर अध्यर्पित किया जाय जैसा कि मुख्य कार्मिक अधिकारी, कलकत्ता के आदेश स० 6469 (सभी भारतीय रेलो के महाप्रबधको तथा अन्य को भेजा गया रेलवे बोर्ड का 27 जुलाई, 1966 का पत्र सं० ई (एन जी) 66 टी आर 2/20) मे उल्लिखित है ।

(8) यह कि, अत मे, समग्र स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराये बिना हम निहित स्वार्थो द्वारा उच्च अधिकारियो के निर्णयो को तोड मरोड कर कार्यवाही करने की निन्दा करते है । इस मुद्दे को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमे यह कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने मुगलसराय के लिए कर्मचारियो के नामो की सूची तैयार करने तथा उन्हे कार्यमुक्त करने मे जल्दबाजी की है और ऐसा करने मे उसने स्थानान्तरण के मानदड अर्थात् कोटि का सबसे कनिष्ठ कर्मचारी पहले जाये, का ध्यान नही रखा है । उन्होने मंडल कार्यालय भवन के बाहर लेकिन मडल क्षेत्र के अन्तर्गत स्कूलो और अधीनस्थ कार्यालयो के कर्मचारियो को एक बार फिर छोड़ दिया है । लेकिन, हम अपने मामले को स्थानीय अधिकारियो के इस तरह के व्यवहार तक सीमित नही रखना चाहते, हमारा मंतव्य केवल उनकी मनोवृत्ति बताना भर है ।

(9) यह कि, दानापुर मडल के लेखा कर्मचारियो के मामले मे कोटि का सबसे कनिष्ठ कर्मचारी का निश्चय करने के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी के निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाय । लेखा कर्मचारियो की वरिष्ठता क्षेत्रीय आधार पर होती है । हो सकता है कि सबसे कनिष्ठ कर्मचारी दानापुर की बजाय कही और काम कर रहा हो । अत : लेखा कर्मचारियो के मामले मे दानापुर मे कनिष्ठता को मार्ग-दर्शक न माना जाय ।

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: The hon Minister has stated that a resolution has been forwarded. Is it not a fact that when the Minister visited there, a deputation waited on him, and gave him a memorandum, and that he gave them the assurance that he would look into these matters and deal with them sympathetically? He now says that the resolution is being examined. Why is it that there is so much delay? He met the deputationists himself on the spot more than 2 months ago. Why this inordinate delay is going into the memorandum and dealing with the problem?

श्री शिव नारायण मैने वहा के वर्करो को बडा आश्वासन दिया और यूनियन के लीडरो को भी हम ने मुनासिब जवाब दिया । वहा दो हजार आदमी थे, मैं ने उन को फेस किया और मै ने यह एलान किया कि जो लोग मुगलसराय जाना चाहे वे जा सकते है और जो न जाना चाहे वे न जाये, यह एश्योरेस दे कर मै आया ।

SHRIMATI PRAVATHI KRISHNAN: He has not answered my question. I asked why this inordinate delay in going into the memorandum. His heroism I do not question, but the fact remains that the matter is still unsolved. In the resolution,

there are three points. One is that some vacancies have been existing in the Denapur division, on the basis of the old yardsticks. Let those vacancies be filled first, before he asks people to move

Second, open, option is to be invited from all over Indian railways for coming to Mughalsarai division, third, that the posts of officers should not be created by matching surrender at all the cost of Class 3 and Class 4 employees On the 28th of September the General Manager had talks with the representatives of the deputation and these points were solved He agreed to them Yet, today they are under consideration This is the kind of delay that goes on and the manner in which the railway employees are being dealt with This is festering sore I want to know positively why it is that the assurance of the General Manager have not been implemented and why this inordinate delay in going into the memorandum

श्री शिव नारायण मैनें पहले भी बताया और फिर बताता हूं कि हमारी यूनियन वालों से बड़ी कार्डियल टाक हुई—इधर वालों से और उधर वालों से भी । मैं ने बिना अपने रेल मंत्री को कसल्ट किए उनको एश्योरेंस दिया कि उनका ट्रांसफर नहीं होगा , कोई कंपलशन नहीं होगा । मैं ने जनरल मनेजर को कमन्ट किया और 3 तारीख को मैं फिर मुगलसराय जा रहा हूं ।

श्री चन्द्र देव वर्मा क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इमर्जेन्सी के दिनों में भूतपूर्व रेल मंत्री ने इस अनुचित निर्णय को लेकर दानापुर के बहुत निकट गया जैसे प्रमुख स्टेशन को भी मुगलसराय में डाल दिया जिस के चलते वहां के लोगों को अपार क्षति होने वाली है ?

श्री शिव नारायण इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

निःशुल्क रेलवे पास

*194. **श्री उग्रसेन :**

श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या रेल मंत्री आपात स्थिति के दौरान सामान्य व्यक्तियों को निःशुल्क रेलवे पास देने के बारे में 5 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको रेल मंत्रालय ने निःशुल्क पास जारी किए हुए है,

(ख) मानार्थ कार्ड पास जारी करने के मापदंड क्या है और इस सम्बन्ध में नई सरकार की क्या नीति है और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के निःशुल्क पास जारी करना बंद करने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) 87 (76 पहले दर्जे के और 11 दर्जे के)

(ख) मानार्थ पास जारी करने के बारे में मोटे तौर पर जो मार्गदर्शक सिद्धांत निश्चित किये गये है, वे इस प्रकार हैं —

(1) सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेल-कूद एवं शैक्षणिक क्रिया-कलापों में सम्बद्ध संस्थाएं और संगठन जिनका कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय स्तर का है ।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे और उपेक्षित समुदायों, महिलाओं, अंधों और अपंग व्यक्तियों आदि के कल्याण से सम्बद्ध संगठन ।

(3) राष्ट्रीय महत्व के काम में लगे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें अपने काम